



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313]
No. 313]नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 10, 2008/फाल्गुन 20, 1929
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 10, 2008/PHALGUNA 20, 1929

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2008

का.आ. 463(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 114(अ), दिनांक 19 फरवरी, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के द्वारा तटीय क्षेत्र के तटीय विनियमन क्षेत्र के रूप में घोषित किया था और उक्त क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने और उनके विस्तार प्रचालन और प्रक्रियाओं पर निर्बंधन आधरोपित किए गए थे;

और, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के संघशासित क्षेत्र में अण्डमान निकोबार प्रशासन द्वारा उक्त संघशासित क्षेत्र के तटीय विनियमन क्षेत्र में बालू के खनन पर उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा लगाए गए निर्बंधनों के और द्वीप समूह में वैकल्पिक निर्माण सामग्री उपलब्ध न होने के कारण उक्त क्षेत्र के स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सहन की जा रही कठिनाइयों की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 के संबंध में अपने दिनांक 7 मई, 2005 के आदेश में अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के बालू के खनन हेतु आदेश पारित किया है;

और, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे की जांच की गई है;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेशों को प्रभावी बनाने के लिए उक्त अधिसूचना में संशोधन किया जाना चाहिए;

और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) में यह उपबंध है कि उप-नियम (3) में किसी बात

के होते हुए भी जब कभी केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह उक्त नियमों के उप-नियम (5) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकती है;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन हेतु उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) और (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में :-

(क) पैरा 2 के उप-पैरा (ix) के उपबंध को निम्नलिखित उपबंध से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“बशर्ते कि अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के संघ शासित क्षेत्र के निर्माण कार्यों के लिए मामला दर मामला आधार पर अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल द्वारा गठित समिति, जिसमें (1) मुख्य सचिव, अण्डमान निकोबार प्रशासन; (2) सचिव, पर्यावरण विभाग; (3) सचिव, जल संसाधन विभाग; और (4) सचिव, अण्डमान लोक निर्माण विभाग शामिल होंगे, द्वारा बालू खनन की अनुमति दी जा सकती है;

इसके अतिरिक्त 31 दिसम्बर, 2008 तक खनन की जाने वाली बालू की कुल मात्रा 22,581 घन मीटर से ज्यादा नहीं होगी और यह कि बालू खनन केवल सागर प्रबंधन संस्थान, चैन्नई द्वारा संवर्धी क्षेत्रों के रूप में अभिनिर्धारित किए गए

क्षेत्रों में किया जाएगा और यह बालू के पनुर्भरण या जमाव की मात्रा पर आधारित होगा ;

इसके अलावा यह भी कि बालू के खनन के संबंध में इस उप-पैरा के अंतर्गत दी जाने वाले मंजूरी खनन योजनाओं पर आधारित होगी और इसमें संवेदनशील तटीय पारिप्रणलियों जैसे कि प्रवाल, कछुए, मगरमच्छ, पक्षियों के विश्रामस्थल तथा संरक्षित क्षेत्रों को नुकसान से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय निर्धारित करने होंगे।

इसके अतिरिक्त यह भी कि तटीय क्षेत्र में लगातार बालू खनन के कारण पारिस्थितिकी को हुए नुकसान का ध्यान में रखते हुए अण्डमान निकोबार प्रशासन द्वारा एक वर्ष की अवधि के भीतर वैकल्पिक निर्माण सामग्री की पहचान की जाएगी और 31 मार्च, 2008 के बाद तटीय विनियमन जोन में बालू खनन हेतु आगे कोई विस्तार नहीं किया जाएगा अथवा मंजूरी नहीं दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त खनन कार्यों और संघर्शासित प्रशासन द्वारा किए गए पर्यावरणीय उपायों की निगरानी के लिए एक निगरानी समिति गठित की जाएगी। निगरानी समिति में संघर्शासित प्रशासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर और अण्डमान निकोबार के एक गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक तिमाही निगरानी रिपोर्ट पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजी जाएगी।” ;

(ख) “तटीय विनियमन क्षेत्र-IV अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह” शीर्ष के अधीन अनुबंध-1 में मद (iv) की उप-मद (ख) में “31 दिसम्बर, 2007” अंकों और शब्द के स्थान पर “1 जनवरी, 2008”, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. जैड-12011/2/96-आई ए-III]

डॉ. नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक ‘जी’

टिप्पणी : प्रमुख अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 114 (अ), दिनांक 19 फरवरी, 1991 द्वारा प्रकाशित की गई थी और बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत संशोधित की गई:

1. का.आ. 595(अ), दिनांक 18 अगस्त, 1994
2. का.आ. 73(अ), दिनांक 31 जनवरी, 1997
3. का.आ. 494(अ), दिनांक 9 जुलाई, 1997
4. का.आ. 334(अ), दिनांक 20 अप्रैल, 1998
5. का.आ. 873(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 1998
6. का.आ. 1122(अ), दिनांक 29 दिसम्बर, 1998
7. का.आ. 988(अ), दिनांक 29 सितम्बर, 1999
8. का.आ. 730(अ), दिनांक 4 अगस्त, 2000
9. का.आ. 900(अ), दिनांक 29 सितम्बर, 2000
10. का.आ. 329(अ), दिनांक 12 अप्रैल, 2001

11. का.आ. 988(अ), दिनांक 3 अक्टूबर, 2001
12. का.आ. 550(अ), दिनांक 21 मई, 2002
13. का.आ. 1100(अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2002
14. का.आ. 52(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2003
15. का.आ. 460(अ), दिनांक 22 अप्रैल, 2003
16. का.आ. 635(अ), दिनांक 30 मई, 2003
17. का.आ. 636(अ), दिनांक 30 मई, 2003
18. का.आ. 563(अ), दिनांक 24 जून, 2003
19. का.आ. 838(अ), दिनांक 24 जून, 2003
20. का.आ. 86(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2005
21. का.आ. 108(अ), दिनांक 13 जुलाई, 2006
22. का.आ. 451(अ), दिनांक 26 मार्च, 2007

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2008

S.O. 463(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.114(E), dated the 19th February, 1991 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government declared coastal stretches as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone;

And whereas the Andaman and Nicobar Administration of the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands has drawn the attention of the Central Government to the difficulties being faced by the local population of the said territory due to lack of alternative construction materials available in the islands and the restrictions imposed by the aforesaid notification on mining of sand in the Coastal Regulation Zone in the said territory;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide its Order dated 7th May, 2005 in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995 has passed Orders on mining of sand in Andaman and Nicobar Islands;

And whereas the issue has been examined by the Government of India in the Ministry of Environment and Forests;

And whereas the Central Government is of the opinion that the said notification should be amended with a view to give effect to the aforesaid Orders of the Supreme Court;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that notwithstanding anything contained in sub-rule (3), wherever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (5) of the aforesaid rules;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in public interest to dispense with the said requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the aforesaid rules for amending the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rules (3) and (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:—

In the said notification,

(a) in paragraph 2, in sub-paragraph (ix), for the provisos, the following provisos shall be substituted, namely:—

“Provided that in the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands, mining of sand may be permitted for construction purpose on a case to case basis by a committee constituted by the Lieutenant Governor of the Andaman and Nicobar Islands consisting of - (1) the Chief Secretary, Andaman and Nicobar Administration; (2) Secretary, Department of Environment; (3) Secretary, Department of Water Resources; and (4) Secretary, Andaman Public Works Department:

Provided further that the total quantity of sand to be mined shall not exceed 22,581 cubic metres for the period ending on the 31st December, 2008 and that sand mining shall be undertaken only in those areas identified as accreting areas by the Institute for Ocean Management (IOM), Chennai and based on rate of replenishment or deposition of sand:

Provided also that the permission as may be granted under this sub-paragraph for mining of sand shall be based on mining plans and shall stipulate sufficient safeguards to prevent damage to the sensitive coastal eco-system including corals, turtles, crocodiles, birds nesting sites and protected areas:

Provided also that in view of the ecological damage due to the continuing sand mining in the coastal area, the Andaman and Nicobar Administration shall identify alternate construction materials within the period of one

year and no further extension or permission to the sand mining in the Coastal Regulation Zone will be accorded after the 31st December, 2008:

Provided also that a Monitoring Committee shall be constituted for monitoring the mining activity and the environmental safeguards taken, by the Union Territory Administration. The Monitoring Committee shall comprise of representatives from the Union Territory Administration, Regional Office of the Ministry of Environment and Forests, Bhubaneswar and a Non-Governmental Organization based at Andaman and Nicobar. The monitoring report shall be sent quarterly to the Ministry of Environment and Forests.”;

(b) in Annexure-I, under the heading “CRZ-IV relating to the Andaman and Nicobar Islands,” in item (iv), in sub-item (b), for the figures, letters and words “31st day of December, 2007”, the figures, letters and words “1st day of January, 2008” shall be substituted.

[No. Z-12011/2/96-IA.III]

Dr. NALINI BHAT, Scientist ‘G’

Note: The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 114(E), dated the 19th February, 1991 and subsequently amended *vide* notifications:

1. S.O. 595 (E), dated 18th August, 1994
2. S.O. 73 (E), dated 31st January, 1997
3. S.O. 494 (E), dated 9th July, 1997
4. S.O. 334 (E), dated 20th April, 1998
5. S.O. 873 (E), dated 30th September, 1998
6. S.O. 1122(E), dated 29th December, 1998
7. S.O. 998(E), dated 29th September, 1999
8. S.O. 730(E), dated 4th August, 2000
9. S.O. 900(E), dated 29th September, 2000
10. S.O. 329(E), dated 12th April, 2001
11. S.O. 988(E), dated 3rd October, 2001
12. S.O. 550(E), dated 21st May, 2002
13. S.O. 1100(E), dated 19th October, 2002
14. S.O. 52(E), dated 16th January, 2003
15. S.O. 460(E), dated 22nd April, 2003
16. S.O. 635(E), dated 30th May, 2003
17. S.O. 636(E), dated 30th May, 2003
18. S.O. 563(E), dated 24th June, 2003
19. S.O. 838(E), dated 24th July, 2003
20. S.O. 86(E), dated 25th January, 2005
21. S.O. 108(E), dated 13th July, 2006
22. S.O. 451(E), dated 26th March, 2007